

# आवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष-10 अंक-295

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

लखनऊ

बुधवार 23 फरवरी 2022

पृष्ठ - 4

मूल्य-3 रूपया

## संक्षिप्त समाचार

**निजी कालोनियों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवनों के लिए मिल सकेगा लोन**

अवध की आवाज लखनऊ। शहर में निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में अब दुर्लभ आय वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस/एल आई जी मकान खरीदने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें बैंकों से लोन मिल सकेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने मंगलवार को विभिन्न विकास कर्ताओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इसके लिए रास्ता बनाया। बैठक में शामिल बैंक प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के शासनादेश के कारण ईडब्ल्यूएस/एल आई जी के आवंटित भवनों पर लोन दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर ईडब्ल्यू एस/एल आई जी भवनों के आवंटन नियमावली में प्रधानमंत्री आवास योजना के विकल्प के प्राविधान लागू कर दिये जाये तो इन भवनों पर भी लोन दिया जाना सम्भव हो जायेगा। इस पर उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में शासन को प्रेषित करके अडचन को दूर किया जाये। बैठक में वित्त नियंत्रक दीपक सिंह और मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## माफिया अतीक के बेटे समेत सात अपराधियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार का इनाम घोषित

प्रयागराज (वेब वार्ता)। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बन्द माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे समेत सात अपराधियों पर पुलिस ने आपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पच्चीस-पच्चीस का इनाम घोषित किया। फरार चल रहे सातों अपराधियों के खिलाफ करेली थाने में जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पच्चीस-पच्चीस हजार का इनाम घोषित किया। उक्त सभी कुख्यात अपराधी 31 दिसम्बर वर्ष 2021 से फरार है। इस इनाम की राशि को कुख्यात अपराधियों के मुठभेड़ के दौरान मारे जाने पर जांच के बाद पुलिस टीम को दी जा सके।



THE BURGER COMPANY  
RM group of enterprises  
Manas Gupta  
Ravi Raj Singh

YOU ARE CORDIALLY INVITED ON THE

## Grand Opening

OF OUR OUTLET

THE BURGER COMPANY,  
BANDA, UP

THURSDAY FEB 24TH, 2022  
AT 3:00 PM

ADJ. VIVEK SINGH KI KOTHI, CIVIL LINES, BANDA, UP

## अयोध्या में योगी की हुंकार: सत्ता में लौटे तो एक हाथ में विकास की छड़ी दूसरे में होगी बुलडोजर की स्टेयरिंग

अवध की आवाज कृष्ण कुमार मिल्कीपुर अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा में बाबा गोरखनाथ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बुलडोजर वाले बाबा की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, जय श्रीराम के नारों से गूँज उठा प्रांगण।

सभा में कहा कि पांचवें चरण में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शुभारंभ मैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से कर रहा हूँ। मिल्कीपुर की घरती से सूर्यवंश की राजधानी एवं अयोध्या व सरयू मैया को प्रणाम करता हूँ। भारतीय

भी मिल्कीपुर आया था, कहा था राम लला हम लयेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या मंदिर निर्माण सपा, बसपा और कांग्रेस करा सकती थीं और कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर पर ताला लगा दिया था। सपा के कार्यकाल में राम

शिलान्यास कर दिया है। मैंने जो 5 वर्ष में वादा किया था उसको करके मैंने दिखा दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पांच नंबर चौराहा इनायत नगर स्थित मैदान पर मिल्कीपुर भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा के लिए आयोजित चुनावी जनसभा में सीएम ने सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल डोज राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा की 5 साल में केवल अयोध्या में 48 हजार लोगों के आवास बने हैं। समूचे प्रदेश में 43 लाख 50 हजार लोगों को आवास देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं है। किसानों को कर्ज माफ करके उन्हें किसान सम्मान निधि। लगातार प्रदान की जा रही है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के सत्ता में आने पर सपा में आतंकवादियों का बोलबाला होता है और सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ होता है।



अयोध्या क्षेत्र के अतर्गत मिल्कीपुर विधान सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़ा जन सैलाब जय श्री राम के नारों से गूँज उठा। मिल्कीपुर विधान

जनता पार्टी की पहचान रामराज्य की परिकल्पना व अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से होती है। मेरे एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टेयरिंग है। मैं 5 साल पहले

भकों पर गोलियाँ चली थीं। सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे किंतु आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2020 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का

## पति के अवैध संबंधों के शक में पत्नी ने लगाई फांसी

औरैया(वेब वार्ता)। फर्रुख़ थाना क्षेत्र में पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध के शक में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के भांजे की शादी में गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव अबाबर निवासी तीस वर्षीय नीतू की शादी 17 अप्रैल 2008 में हिन्दू रीति रिवाज से फर्रुख़ थाना क्षेत्र के गांव पसईपुर केशमपुर निवासी मनोज कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से सब कुछ सही चलता रहा। पति

मनोज कुमार गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। पत्नी नीतू को शक था कि पति किसी दूरी महिला से बात करता है जिसको लेकर दोनों में आये दिन झगड़ा होता रहता था। पति मनोज 19 फरवरी को गुजरात से गांव आया था। 21 फरवरी दिन सोमवार को मनोज के भांजे की शादी इटावा जनपद के अहेरीपुर गांव में थी। सोमवार को मनोज ने पत्नी से शादी में जाने के लिए कहा, तो पत्नी नीतू ने मना कर दिया। पति दोपहर में अपने दो बच्चों सिंघम व यश को लेकर भांजे की शादी में चला गया तथा पत्नी व एक वर्षीय पुत्र रिषभ को घर पर छोड़ गया। रात्रि में किसी समय पत्नी ने घर में बने कमरे में दीवार में लगे कुंडे से साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जाग गये तब पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो वह फांसी पर लटकी थी। पड़ोसियों ने पति मनोज कुमार को सूचना दी।

## जौनपुर में अंधेड़ महिला की गला रेत कर हत्या

जौनपुर (वेब वार्ता)। सराय खाजा थाना क्षेत्र के भरेठी गांव में मंगलवार एक अंधेड़ महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव एक ट्यूबवेल पंप के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह जब ग्रामीण टहलने के लिए घर से बाहर निकले तो भरेठी गांव में लगे ट्यूबवेल पंप के पास 45 वर्षीय विधवा महिला का घड़ से अलग शव देखा। इस घटना को लेकर गांव में दहशत का माहौल बन गया और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गयी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवानंद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गये। इस बीच एएसपी सिटी संजय कुमार और एएसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। ग्रामीणों ने मृतक महिला

की शिनाख्त कर उसका नाम शीला राजभर बताया है। हत्या किन कारणों से हुई है अभी इस पर परिवार वालों के द्वारा ही कोई को जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एएसपी ने बताया कि प्रथमदृष्टया पुलिस छानबीन में और लोगों से बातचीत के बाद मामला पारिवारिक और जमीनी विवाद का सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस



आगे की कार्रवाई कर रही है।

## घण्टों इन्तजार करती रही जनता नहीं आये माननीय

अवध की आवाज विनोद कुमार गोंडा। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है प्रत्याशियों का जनसम्पर्क और वादा करने का सिलसिला इन दिनों चरम पर है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश तिवारी के समर्थन में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जन सभा प्रस्तावित स्थान धानेपुर राम लीला मैदान होना तय था अकस्मात उनका दौरा रद्द होने की वजह से पब्लिक और पुलिस दोनों हलकान रही। एक तरफ जहां भाजपा और

सपा की लड़ाई आमने सामने है तो वही दूसरी तरफ अन्य पार्टियों

तिवारी भी जनसम्पर्क के दौरान क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे



के कंडिडेट भी मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी राजेश

करते नजर आ रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है क्षेत्र की जनता को मूलमूल सुविधाओं से वंचित रखने के साथ

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें इत्यादि की ब्यवस्था बहुत ही दयनीय है। क्षेत्र की जनता अगर अपना मत दे कर उन्हें विधान सभा भेजती है तो मेहनत को आदर्श विधान सभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगे। उन्होंने भाजपा और उससे पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जैसी मूल मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, यहां के जिम्मेदारों ने केवल अपना विकास किया है। जनता बदलाव चाहती है जो इस बार देखने को मिलेगा।

## मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में डीएम ने छात्र-छात्राओं को दिलाई शपथ

अवध की आवाज विनोद कुमार गोंडा। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय अधिकारी जॉन उज्ज्वल कुमार ने सीडीओ शशांक त्रिपाठी के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत कई कार्यक्रमों मतदाताओं में प्रतिभाग किया। मतदाता जागरूकता को लेकर जिले में ब्लाकों, विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर के रवि विल्डन एकेडमी इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बतौर मुख्य अतिथि छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन के लोग घर-घर पर्वियां बांट रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि 27 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जो भी छात्र-छात्राएं मतदाता हैं वे स्वयं तो वोट दें ही, इसके अलावा अपने

अभिभावकों एवं मित्रों को भी वोट के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं की सूची लेकर बूथ केंद्रों पर बैठे को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। जीजीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में भी छात्राओं को मताधिकार के प्रति जागरूक



रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न हो इसके लिए हर मतदान केंद्र पर भारी फोर्स लगी रहेगी जिससे आप लोग कोई परेशानी न हो। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय एक घन्टा बढ़ाकर सहूलियत दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि इस बार जनपद में हर मतदाता से वोट डलवाना है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि जिनके अभिभावक या रिश्तेदार अथवा मित्रगण जिले के बाहर हैं उन्हें 27 फरवरी को वोट डालने के लिए फोन करके बुलाएं तथा उनसे वोट डलवाएं। कालेज में जिलाधिकारी द्वारा छात्र-छात्राओं

## नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे लोकतंत्र के इस महोत्सव में जरूर हिस्सा लें अधिक से अधिक मतदान करें



भारत निर्वाचन आयोग  
Election Commission of India

**पत्रकार मनोज गुप्ता**  
**अवध की आवाज**

## नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे लोकतंत्र के इस महोत्सव में जरूर हिस्सा लें अधिक से अधिक मतदान करें



भारत निर्वाचन आयोग  
Election Commission of India

**ब्यूरो चीफ गुड्डू मिश्रा**  
**अवध की आवाज**

## सम्पादकीय

# आखिर नसबंदी की जिम्मेवारी भी महिलाओं पर क्यों?

(पुरुष नसबंदी की कम लागत और सुरक्षित प्रक्रिया के बावजूद, भारत की एक तिहाई से अधिक यौन सक्रिय आबादी में महिला नसबंदी को क्यों अपनाया जा रहा है? पुरुष नसबंदी का विकल्प नगण्य—सा है। हमारे राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में 15-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के उपयोग में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और गर्भनिरोधक विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए पितृशक्ततात्मक दृष्टिकोण जारी है।)

प्रजनन अधिकार कानूनी और स्वास्थ्य से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं जो दुनिया भर के देशों में अलग-अलग हैं। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों में कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, यौन नियंत्रण का अधिकार, गर्भनिरोधक से मुक्ति, अर्थात् गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार और मुक्त और सूचित प्रजनन के लिए शिक्षा और पहुंच का अधिकार शामिल हैं। हालाँकि, हमारे देश में महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों की मान्यता अभी भी नगण्य है। महिलाओं के लिए एक सख्त एजेंसी की कमी सबसे बड़ी बाधा है। प्रजनन और यौन अधिकारों की अनुपस्थिति का महिलाओं की शिक्षा, आय और सुरक्षा नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे वे 'अपना भविष्य खुद बनाने में असमर्थ' हो जाती हैं।

वर्तमान में 15-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में गर्भनिरोधक के उपयोग में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है यानी 2015-16 में 53.5 फीसदी से 2019-20 में 66.7 फीसदी हो गई है। कंडोम के उपयोग में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है, जो 5.6 फीसदी से बढ़कर 9.5 फीसदी हो गया। भारत में परिवार नियोजन की अवधारणा की स्थापना के कई वर्षों बाद भी केवल महिला नसबंदी सबसे लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है। पुरुष नसबंदी का विकल्प नगण्य—सा है। कम उम्र में शादी, जल्दी बच्चे पैदा करने का दबाव, परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति की कमी, शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा और पारिवारिक संबंधों में जबरदस्ती के कारण शिक्षा कम होती है और बदले में महिलाओं की आय कम होती है। अपने प्रजनन अधिकारों पर कमी के कारण लगातार बच्चे पैदा करने से वह ज्यादातर एक गृहिणी बन गई है, जिससे वह वित्त के लिए जीवनसाथी पर निर्भर हो गई है। पितृशक्ततात्मक मानसिकता और बच्चों के बीच उचित दूरी के बिना अपेक्षित संख्या में बेटे पैदा होने तक बच्चे को जन्म देना उसे शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है और उसके जीवन को खतरों में डालता है। एक पक्षी के लिए केवल एक समाज में बेवजह ये डर कि

शिक्षित महिलाओं को पति और उसके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उसके शिक्षा अधिकारों को कहीं न कहीं कम कर देता है। पुरुष नसबंदी की कम लागत और सुरक्षित प्रक्रिया के बावजूद, भारत की एक तिहाई से अधिक यौन सक्रिय आबादी के साथ महिला नसबंदी सबसे व्यापक प्रसार विधि है। भारत में प्रजनन अधिकारों को बाल विवाह, कन्या मरुण हत्या, लिंग चयन और मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों जैसे चुनिंदा मुद्दों के संदर्भ में ही समझा जाता है। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, उनके पोषण की स्थिति, कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के जोखिम पर ध्यान देना चिंता का संवेदनशील मुद्दा है और अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है तो इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारत में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को संबोधित करने और पहचानने के लिए उचित कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए उपयुक्त, सरसती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और संबंधित सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य सहित महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के सभी मुद्दों की देखभाल करने के लिए प्रजनन अधिकार अधिनियम के रूप में कानून बनाने चाहिए वह विकिसा सुविधाएं प्रदान करने या जागरूकता पैदा करने के संबंध में हो या महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम का। इसलिए, यह समय की मांग है कि नीति और व्यापक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। बेहतर और स्वस्थ प्रजनन व्यवहार को बढ़ावा देना जो लड़कियों और युवाओं को जीवन रक्षक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करे।

सार्वजनिक बहस और मांगों में इन मुद्दों को लाने के लिए नागरिक समाज की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं ने लैंगिक अंतर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के साथ कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। फिर भी महिलाओं और लड़कियों की तस्करी, मातृ स्वास्थ्य, हर साल गर्भपात से होने वाली मौतों की वास्तविकताओं ने उन सभी विकासों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, 'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है।'

—राम पुनिया—

हिजाब के मुद्दे पर शुरू हुए विवाद ने गंभीर और चिंताजनक स्वरूप अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कालेज ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश देने से इंकार कर दिया। उसके बाद कालेज ने हिजाबधारी को आतंकित करने के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। जिन लोगों ने सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई जैसे मोबाईल एप बनाए थे और जो धर्मसंसदों में कही गई बातों से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी भी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। वे जानते हैं कि हिजाब मुद्दे से देश में साम्प्रदायिक छ्बीकरण बढ़ेगा। मोहन भागवत का यह कहना कि वे धर्मसंसद में कही गई बातों से सहमत नहीं हैं केवल जनता की आंखों में धूल झांकना है। आरएसएस के इन्ड्रेश कुमार, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पथप्रदर्शक हैं, ने यह कहकर मुस्कान की निंदा की है कि उसने शांति भंग करने का प्रयास किया। हमने यह भी देखा है कि देश के कई इलाकों में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि नरसंहार विशेषज्ञ गेगरी स्टैनटन ने चेतावनी दी है कि नरसंहार के मामले में 1 से 10 अंकों के स्केल पर भारत 8वें अंक पर है। इसके पहले देश पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी लादे गए

करें तो गोवा में कांग्रेस पार्टी ने 40 में से 36 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 सीटें जीती थी। वहां कांग्रेस को दो लाख 59 हजार 758 वोट यानि 28.4 प्रतिशत वोट मिले थे। जबकि वहां भाजपा मात्र 13 सीटों पर ही जीत पाई थी। उसके उपरांत भी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह की ढिलाई के चलते सत्ता के नजदीक पहुंच कर भी कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार गोवा में कांग्रेस ने गोवा फारवर्ड पार्टी से चुनावी गठबंधन कर चुनाव लड़ा है। हालांकि गोवा में कांग्रेस को फेर से सरकार बनाने की संभावनाएं बताई जा रही है।

2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जहां भारी बहुमत से पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं गोवा व मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अपनी रणनीतिक चूक के चलते सरकार बनाने से रह गई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी को अपने प्रभाव वाले प्रदेशों में पहले से ही ऐसी सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। जहां बहुमत के करीब होने पर अपनी सरकार का गठन कर सके। ना कि पिछली बार की तरह बहुमत के करीब होने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाए।

2017 के विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजों का विश्लेषण

के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। जो कुछ हो रहा है उससे आक्रामक हिन्दुत्ववादी समूह बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें उनका एजेंडा आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। यह भी साफ है कि मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। जिन लोगों ने सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई जैसे मोबाईल एप बनाए थे और जो धर्मसंसदों में कही गई बातों से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी भी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। वे जानते हैं कि हिजाब मुद्दे से देश में साम्प्रदायिक छ्बीकरण बढ़ेगा। मोहन भागवत का यह कहना कि वे धर्मसंसद में कही गई बातों से सहमत नहीं हैं केवल जनता की आंखों में धूल झांकना है। आरएसएस के इन्ड्रेश कुमार, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पथप्रदर्शक हैं, ने यह कहकर मुस्कान की निंदा की है कि उसने शांति भंग करने का प्रयास किया। हमने यह भी देखा है कि देश के कई इलाकों में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि नरसंहार विशेषज्ञ गेगरी स्टैनटन ने चेतावनी दी है कि नरसंहार के मामले में 1 से 10 अंकों के स्केल पर भारत 8वें अंक पर है। इसके पहले देश पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी लादे गए

जिससे ऐसा वातावरण बना मानों मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया गया और यही सीएए के खिलाफ हुए आंदोलनों के मामले में भी हुआ। यह सब अत्यंत निंदनीय है। हमें कुछ मुद्दों पर सावधान रहने की जरूरत है। हिन्दू दक्षिणपंथियों को मुस्लिम साम्प्रदायिकता और अतिवाद से बढ़ावा मिलता है, क्या हिजाब मुद्दे पर छिड़े विवाद में मुस्लिम साम्प्रदायिक ताकतों की भागीदारी है? इस सिलसिले में हमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की विद्यार्थी शाखा कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों को भी ध्यान में रखना होगा। यह संगठन केरल में प्रोफेसर जोसफ पर हमले के पीछे था। यह समझना मुश्किल है कि एक लंबे समय से चली आ रही वह व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लड़कियां स्कूल पहुंचने तक हिजाब पहने रहती थीं और कक्षा में जाने पर उसे उतार देती थीं, को बदलने की भला क्या जरूरत पड़ेगी? एक ओर से नारे लगाए जा रहे हैं कि 'हिजाब पहनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' तो दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि 'देश शरिया के आधार पर नहीं चल सकता'। हिजाब पूरी दुनिया में बहस का विषय रहा है। जब फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने को प्रतिबंधित किया गया तब इसका जबरदस्त विरोध हुआ परंतु सरकोजी अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। कई मुस्लिम-बहुल देशों

में भी सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब प्रतिबंधित है। इनमें शामिल हैं कोसोवो (सन् 2008 से), अजरबैजान (2010), ट्यूनिशिया (1981), यद्यपि 2001 में इसे आंशिक रूप से उठा लिया गया) व तुर्की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा की है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढंकने वाला अबाया पहनना अनिवार्य नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, मालदीव और सोमालिया में भी यह अनिवार्य नहीं है। अलबत्ता ईरान, अफगानिस्तान एवं इंडोनेशिया के आवेह प्रांत में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अबाया पहनना कानूनन आवश्यक है। भारत में स्थिति कहीं जटिल है। देश में बुर्का और हिजाब का प्रचलन काफी पहले से था परंतु बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद इसके प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर खाड़ी क्षेत्र के तेल संसाधनों पर कब्जा जमाने के अमरीका के अभियान और उससे जनित 'इस्लामिक आतंकवाद' की संकल्पना ने मुसलमानों में असुरक्षा के भाव को बढ़ाया।

बुर्का और हिजाब के प्रचलन में बढ़ोत्तरी का एक कारण भारतीयों का खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए जाना भी है। जिस समय भारतीय काफी बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में जाया करते थे उस समय वहां बुर्का और हिजाब अनिवार्य था।

जब ये लोग भारत लौटे तो अपने साथ हिजाब और बुर्के की अनिवार्यता का विचार भी ले आए। इन दिनों कई मुस्लिम अभिभावक लड़कियों को बचपन से ही हिजाब/बुर्का पहनाते हैं। इससे उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। उन्हें यह भी लगता है कि ऐसा करके वे अपने परिवार और समुदाय की भावनाओं का सम्मान कर रही हैं। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। परंतु समस्या यह है यदि पांच वर्ष की आयु से किसी लड़की को हिजाब पहनाया जायेगा तो वह उसकी 'इच्छा' बन जायेगा। इस्लाम के कुछ अध्येताओं का मत है कि कुरान के अनुसार, लड़कियों के लिए किशोरावस्था में कदम रखने के बाद से हिजाब पहनना जरूरी है। असगर अली इंजीनियर और जीनत शौकत अली जैसे इस्लाम के जानकारों के अनुसार कुरान में नकाब और बुर्के का कहीं जिक्र ही नहीं है। हाँ, उसमें हिजाब (सात स्थानों पर) का जिक्र अवश्य है परन्तु उसका इस्तेमाल आड़ के तौर पर किया जाना है, गर्दन और चेहरे को ढंकने के लिए नहीं। हिजाब की तरह के वस्त्र कई समुदायों में इस्तेमाल होते हैं। ईसाई नर्से, यहूदी और अन्य कई समुदायों की स्त्रियाँ हिजाब से

मिलते-जुलते वस्त्र का प्रयोग करती हैं। भारत में भी एक समय घूंघट का व्यापक प्रचलन था यद्यपि समय के साथ इसमें तेजी से कमी आई है। दरअसल, घूंघट, हिजाब इत्यादि के मूल में महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण करने की पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति है। रूपकुंवर के सती हो जाने के बाद, भाजपा की तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयाराजे सिंधिया के नेतृत्व में संसद के सामने प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि सती होना हिन्दू महिलाओं का अधिकार है! इस दौर में हिजाब जैसे मुद्दों पर विवाद खड़ा करना मुस्लिम लड़कियों के शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर करना है। इससे शिक्षा के जरिये उनके सशक्तिकरण में बाधा आएगी। मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है वह उसमें व्याप्त असुरक्षा के भाव का नतीजा है। अगर अदालत हिजाब के पक्ष में फैसला सुनाती है तो इससे मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा हासिल करने की प्रक्रिया कमजोर होगी। हिन्दू दक्षिणपंथी अत्यंत शक्तिशाली हैं। मुस्लिम दक्षिणपंथी, लोगों को भड़का कर हिन्दू दक्षिणपंथियों को मजबूत कर रहे हैं। इससे असल नुकसान मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम समुदाय का होगा। क्या हम इसे रोक सकते हैं? (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

# कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण पांच राज्यों का चुनाव, जनाधार में हो सकती है बढ़ोत्तरी

—रमेश सर्राफ़ धमोरा—

देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इन पांच राज्यों में से उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी चार राज्यों में कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनावी मुकाबले में है। फिलहाल पांच में से चार राज्यों में भाजपा व पंजाब में कांग्रेस पार्टी का शासन है। कांग्रेस पार्टी इन सभी पांच राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके अपने घटते जनाधार को रोक सकती है। पंजाब के साथ ही उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने की संभावनाएं बताई जा रही है।

2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जहां भारी बहुमत से पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं गोवा व मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अपनी रणनीतिक चूक के चलते सरकार बनाने से रह गई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी को अपने प्रभाव वाले प्रदेशों में पहले से ही ऐसी सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। जहां बहुमत के करीब होने पर अपनी सरकार का गठन कर सके। ना कि पिछली बार की तरह बहुमत के करीब होने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाए।

2017 के विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजों का विश्लेषण

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से मात्र 11 सीटें ही जीत सकी थी। उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण व किच्छा दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। 2017 में कांग्रेस को 16 लाख 65 हजार 64 यानी 33.5 प्रतिशत मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। जिससे कांग्रेसी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सविता आर्य का अग्रिम नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटके भी लगे हैं। चार बार मुख्यमंत्री व 50 साल तक विधायक रह चुके प्रतापसिंह राणे इस बार पर्ये विधानसभा सीट पर कांग्रेस टिकट मिलने के बावजूद भाजपा से अपनी पुत्रवधू डॉ दिव्या रानी के उम्मीदवार बनने पर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इससे कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। जबकि कांग्रेस इस बार गोवा में अपनी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार बनाने के प्रति काफी आशान्वित हैं। इससे वहां भी अभी से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में खींचतान शुरू हो गई है। पिछले

था। मगर आज वहां के सभी आठों प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इसलिए मणिपुर के रास्ते कांग्रेस एक बार फिर पूर्वोत्तर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लिए इस बार पंजाब में बड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति हो रही है। 2017 में कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती थी तथा 38.50 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के एक छात्र नेता होते थे। मगर अब पंजाब में कांग्रेस की स्थिति एकदम से बदल गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर होकर भाजपा के साथ गठबंधन कर अपनी अलग पार्टी बना कर उससे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यशपाल आर्य व उनके पुत्र संजीव आर्य को भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल करवा लिया था। मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 28 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा ने मात्र 21 सीटें जीती थी। मगर कांग्रेस के नेताओं की कमजोरी के चलते वहां भाजपा की सरकार बन गई थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 35.10 प्रतिशत वोट मिले थे। मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेसी इस बार पूरी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार मणिपुर में सरकार बनाने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाह रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर में कभी कांग्रेस का एकछत्र राज होता

था। मगर आज वहां के सभी आठों प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इसलिए मणिपुर के रास्ते कांग्रेस एक बार फिर पूर्वोत्तर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लिए इस बार पंजाब में बड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति हो रही है। 2017 में कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती थी तथा 38.50 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के एक छात्र नेता होते थे। मगर अब पंजाब में कांग्रेस की स्थिति एकदम से बदल गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर होकर भाजपा के साथ गठबंधन कर अपनी अलग पार्टी बना कर उससे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यशपाल आर्य व उनके पुत्र संजीव आर्य को भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल करवा लिया था। मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 28 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा ने मात्र 21 सीटें जीती थी। मगर कांग्रेस के नेताओं की कमजोरी के चलते वहां भाजपा की सरकार बन गई थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 35.10 प्रतिशत वोट मिले थे। मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेसी इस बार पूरी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार मणिपुर में सरकार बनाने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाह रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर में कभी कांग्रेस का एकछत्र राज होता

कांग्रेस ने पंजाब में 8 उत्तर प्रदेश व गोवा में एक-एक सीटें जीती थी। पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में इन पांच राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करो या मरो की नीति पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्चस्व इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ही टिका हुआ है। यदि कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में पहले से अच्छा प्रदर्शन कर दिखाती है तो कांग्रेस को लिए पूरे देश में संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद कांग्रेस को पंजाब में कुछ बढ़ा कर दिखाना होगा। तभी पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं के पलायन पर रोक लग सकेगी व कांग्रेस फिर से मुख्यधारा में शामिल हो पाएगी। इन पांच राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिये किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं हैं। जिसमें चूकने का मतलब है सब कुछ समाप्त हो जाना। ऐसे में चुनाव जीतने के लिये पार्टी के नेताओं को पूरा दम लगा कर काम करना होगा। (लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनके लेख देश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।)





